



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

19 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 786 राँची, शुक्रवार,

11 अक्टूबर, 2019 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----  
संकल्प

4 अक्टूबर, 2019

**विषय:-** केन्द्र प्रायोजित अमृत योजना अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं अंतर्गत भुगतान हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में ICICI Payment Gateway (M/s ICICI Bank Ltd.) से एकरारनामा करते हुए मनोनयन के आधार पर सेवा लेने के संबंध में।

**संख्या :-** SUDA/AMRUT/Web Service-36/2016 (खंड संचिका)-5018-- 74 वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में शहरी निकायों के द्वारा नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग संवैधानिक दायित्व है। अतः नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य के सभी नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करने हेतु कृत संकल्प है।

2. अमृत योजना के शहरी सुधारों के अंतर्गत e-Governance सेवाओं के अधीन राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के नागरिकों को विभिन्न ऑनलाईन सेवाएँ, यथा-Building Plan, Water Connection, Trade License एवं Property Tax की सुविधा website के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

3. इस क्रम में नागरिकों को सुविधा शुल्क/कर भुगतान हेतु ऑनलाईन Payment की सुविधा राँची नगर निगम में ICICI Payment Gateway एवं शेष निकायों में NDML/Billdesk के माध्यम से दी जा रही है। NDML/Billdesk के माध्यम से online payment में आम नागरिकों को हो रही परेशानी, यथा-नागरिकों द्वारा online payment के बाद भी पोर्टल पर Application update नहीं होना, दो बार online Payment हो जाना एवं उक्त के reconciliation की पर्याप्त सुविधा नहीं रहने की स्थिति में अन्य विकल्प की आवश्यकता है।

4. पिछले तीन वर्षों से राँची नगर निगम में ICICI Payment Gateway के माध्यम से कर संग्रहण सुव्यवस्थित रूप से संचालित है, जो MIS पर भी परिलक्षित होता है। इसके साथ ही ICICI Payment Gateway द्वारा Reconciliation Service की नियमित सुविधा दी जाती है।

5. Payment Gateway सेवाएँ हेतु SBI एवं ICICI Bank के माध्यम से Online Transaction हेतु Chargeable Amount एवं Reconciliation Service Support की तुलना में ICICI Payment Gateway को नागरिकों हेतु श्रेष्ठकर पाया गया है।

6. ICICI Payment Gateway के माध्यम से कर संग्रहण हेतु विभाग को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं वहन करना पड़ेगा। उक्त क्रम में सुविधाएँ, जैसे-ICICI Software Application, Reconciliation Service, MIS Transaction Report की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। ICICI Payment Gateway हेतु ESCROW Account खुलवाया जाएगा। यह ESCROW Account ICICI Bank के माध्यम से Pool Account के रूप में रहेगी। आम लोगों द्वारा online कर का भुगतान करने पर राशि Pool Account से होते हुए (T+2 दिन) शहरी स्थानीय निकायों के संबंधित बैंक खाताओं में Transfer होगी। Pool Account एक ESCROW Account है, जो अपने आप में एक Auditable Account है, जिससे विभाग किसी भी समय Audit करा सकता है। ICICI Online Application के माध्यम से प्रत्येक दिन का Transaction रिपोर्ट परिलक्षित होगा एवं Online Transaction Report नियमित रूप से online माध्यम से प्राप्त किया जायेगा।

7. वर्णित परिपेक्ष्य में केन्द्र प्रायोजित अमृत योजना अंतर्गत नागरिकों की सहायता के लिए राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न ऑनलाईन सेवाओं अंतर्गत भुगतान हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में ICICI Payment Gateway (M/s ICICI Bank Ltd.) संस्थान से एकरारनामा करते हुए मनोनयन के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं एकरारनामा प्रारूप पर विधि विभाग की विधिक्षा प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति प्राप्त है।

11. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 01.10.2019 में मद सं० 07 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अजय कुमार सिंह,**  
सरकार के सचिव।

-----